



KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

सरकारी योजनाएं

by : SKC Sir

सरकारी योजनाएं करंट अफेयर्स

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में "पीएम विश्वकर्मा" योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना है। इसे 13,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा।

कारिगरों, जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है, को बायोमेट्रिक-आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में पंजीकृत किया जाएगा।

विश्वकर्मा को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दरों पर संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट सहायता के माध्यम से मान्यता प्राप्त होगी।

यह योजना गुरु-शिष्य परंपरा (शिक्षक-छात्र परंपरा) को संरक्षित करने और कारिगर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है।

इसमें 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं, जिनमें बढईगीरी, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और बहुत कुछ शामिल हैं।

यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों कारिगरों को लक्षित करती है।

इसका उद्देश्य कारिगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।

पीएम विश्वकर्मा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेंगे और कारिगरों और शिल्पकारों को विपणन सहायता प्रदान करेंगे।

प्रश्न: पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (A) आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देना
- (B) पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारिगरों का समर्थन करना
- (C) कृषि उत्पादकता बढ़ाना
- (D) पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना

उत्तर: (B) पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारिगरों का समर्थन करना

कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना को तीन साल के लिए विस्तार को मंजूरी दी

सरकार ने 13 सितंबर 2023 को एक कैबिनेट बैठक के दौरान महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए सहायता प्रदान करने वाली योजना पीएम उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों की अवधि में कुल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करना है।

योजना का कुल वित्तीय निहितार्थ एक हजार 650 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित करने के लिए 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

आज तक, उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं, जो इसके व्यापक प्रभाव और पहुंच को दर्शाता है।

प्रश्न: पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है?

- (A) एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना
- (B) महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना
- (C) एलपीजी की कीमतें कम करना
- (D) एलपीजी सिलेंडर सुरक्षा बढ़ाना

उत्तर: (B) महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना

मेरा बिल मेरा अधिकार : चालान प्रोत्साहन योजना

चालान प्रोत्साहन योजना – मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है। योजना का उद्देश्य आम जनता में एक बिल को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है।

योजना का नाम: चालान प्रोत्साहन योजना – मेरा बिल मेरा अधिकार

उद्देश्य: जनता को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना।

प्रारंभिक पायलट: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के साथ-साथ असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में पायलट के रूप में लॉन्च किया गया।

उपभोक्ता पुरस्कार: उपभोक्ताओं के पास एक करोड़ रुपये का आकर्षक इनाम जीतने का मौका है।

पात्रता: जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी व्यवसाय से ग्राहक चालान इस योजना के लिए पात्र होंगे।

न्यूनतम चालान मूल्य: लकी ड्रा के लिए न्यूनतम दो सौ रुपये मूल्य वाले चालान पर विचार किया जाएगा।

चालान जमा करना: चालान मोबाइल एप्लिकेशन "मेरा बिल मेरा अधिकार" या वेब पोर्टल "merabill.gst.gov.in" का उपयोग करके अपलोड किया जा सकता है।

प्रतिभागी पात्रता: भारत के सभी निवासी भाग ले सकते हैं, चाहे उनका राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कुछ भी हो।

मासिक अपलोड सीमा: लकी ड्रा के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकता है।

मासिक इनाम: सरकार हर महीने 800 व्यक्तियों का चयन करेगी और प्रत्येक को दस हजार रुपये का इनाम मिलेगा।

बम्पर ड्रा: त्रैमासिक बम्पर ड्रा आयोजित किया जाएगा, जिसमें दो लोग एक-एक करोड़ रुपये का इनाम जीतेंगे।

योजना अवधि: पायलट योजना 12 महीने की अवधि तक चलेगी।

प्रश्न: आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है?

- (A) बिल पुरस्कार पहल
- (B) मेरा बिल मेरा अधिकार
- (C) राजकोषीय व्यवहार प्रोत्साहन
- (D) इनवॉइस कल्चर ड्राइव

उत्तर : (B) मेरा बिल मेरा अधिकार

सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कीं

सरकार ने 29 अगस्त 2023 को सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती की घोषणा की है।

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए बढ़ा हुआ लाभ: सरकार की पहल, उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रति एलपीजी सिलेंडर में 400 रुपये की कटौती की गई है।

उज्ज्वला योजना का विस्तार: सरकार की योजना उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की है।

उज्ज्वला योजना का उद्देश्य: उज्ज्वला योजना का उद्देश्य घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करना और गरीब परिवारों के बीच स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे अंततः कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाया जा सके।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 01.05.2016 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य रखा था।

प्रश्न: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) गरीब परिवारों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना
 - (B) महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश
 - (C) गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना
 - (D) ग्रामीण समुदायों को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करना
- उत्तर: (C) गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करें

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने 28 अगस्त, 2023 को 9 साल पूरे कर लिए

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने 28 अगस्त, 2023 को नौ साल पूरे कर लिए। जन धन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। योजना शुरू होने के बाद से 50 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं। जन-धन खाताधारकों में लगभग 56% महिलाएँ हैं, और लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। जनधन खातों में कुल जमा राशि दो लाख तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है। जनधन खाताधारकों को 33 करोड़ से अधिक RuPay कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग छह करोड़ 26 लाख खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) क्या है

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को देश के सभी घरों तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के

उद्देश्य से की गई थी, खासकर उन लोगों को जिन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखा गया था। जन धन योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन: यह योजना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक खाते तक पहुंच हो, जिससे वित्तीय सेवाएं समाज के सबसे वंचित वर्गों तक भी पहुंच योग्य हो सकें।

बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच: योजना के तहत, खाताधारकों को एक बुनियादी बचत खाता, एक रुपये डेबिट कार्ड और जमा और निकासी सेवाओं जैसी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): जन धन खातों का उपयोग अक्सर विभिन्न सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए किया जाता है। इससे लीकेज को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

ऋण सुविधाएं: यह योजना वंचित आबादी के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण उपलब्धता को भी बढ़ावा देती है। यह बैंकों को एक निश्चित अवधि के बाद खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें आपातकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

बीमा और पेंशन योजनाएं: जन धन खाताधारक सरकार समर्थित बीमा और पेंशन योजनाओं के लिए भी पात्र हैं, जो उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना: इस योजना का उद्देश्य जनता के बीच बचत और वित्तीय अनुशासन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (A) ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना
- (B) कृषि उत्पादकता बढ़ाना
- (C) डिजिटल मनोरंजन सेवाओं को बढ़ावा देना

(D) सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना

उत्तर: (D) सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना

पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक श्रमिकों के लिए एक बढ़ावा

पीएम विश्वकर्मा योजना मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारगिरी, निर्माण, सिलाई और नाव निर्माण जैसे पारंपरिक कौशल वाले श्रमिकों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। इस योजना की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 पर की थी और कैबिनेट द्वारा ₹13,000 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। योजना के मुख्य लाभ हैं:

श्रमिकों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से उनके कौशल के लिए औपचारिक मान्यता प्राप्त होगी, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ऋण सुविधाओं और बाजार संबंधों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। श्रमिकों को उनकी उत्पादकता और उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे।

यह योजना भारत के पारंपरिक शिल्प और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा देगी, जो आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर के लगभग 7 करोड़ श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है जो विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं।

प्रश्न: पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- (B) पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना
- (C) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना
- (D) शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

उत्तर: (B) पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना

पीएम-ईबस सेवा: भारत के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की योजना

पीएम-ईबस सेवा भारत के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए 16 अगस्त 2023 को भारत के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य सिटी बस संचालन को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का पालन करेगी, जहां निजी क्षेत्र ई-बसों की खरीद और संचालन में निवेश करेगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।

इस योजना का कुल परिव्यय ₹57,613 करोड़ है, जिसमें से ₹20,000 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना से रोजगार के अवसर पैदा होने, ई-बस विनिर्माण के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलने और ईंधन और कार्बन उत्सर्जन में बचत होने की उम्मीद है

प्रश्न: पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी?

- (A) 5,000
- (B) 10,000
- (C) 15,000
- (D) 20,000

उत्तर: (B) 10,000

प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह ने 1 अगस्त 2023 को बताया कि प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना से लगभग 2.46 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

यह योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण

और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है।

पीएम-कुसुम योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

इस पहल का लक्ष्य 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करके और 10 गीगावॉट वितरित सौर परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है।

पीएम-कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है।

किसानों को ट्यूबवेल और पंप सेट लगाने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी और कुल लागत का 30% सरकार से ऋण के रूप में भी मिलेगा।

यह योजना किसानों को उनकी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है।

यह योजना 08 मार्च 2019 को शुरू की गई थी।

प्रश्न: किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल, पीएम-कुसुम का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) प्रधानमंत्री खेती ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
- (B) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उपकरण महाभियान
- (C) प्रधानमंत्री खेती ऊर्जा सब्सिडी एवं उत्थान महाभियान
- (D) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

उत्तर: (D) पीएम-कुसुम: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

यूके-भारत युवा व्यावसायिक योजना: ब्रिटेन में दो साल तक रहने, काम करने या अध्ययन करने का अवसर

ब्रिटिश सरकार ने यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत दूसरा मतपत्र लॉन्च किया है, जिसमें यूके

वीजा के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों को लक्षित किया गया है।

इस योजना के माध्यम से योग्य युवा भारतीयों को यूके में दो साल तक रहने, काम करने या अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

पात्र होने के लिए, स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता के साथ 18 से 30 वर्ष की आयु का एक भारतीय नागरिक भारत युवा पेशेवर योजना वीजा के लिए आवेदन कर सकता है।

इस योजना के लिए मतदान घोषणा के अगले दिन दोपहर 1.30 बजे बंद हो जाता है।

यूके और भारत के बीच संयुक्त योजना चालू वर्ष के फरवरी में शुरू की गई थी।

उम्मीदवार अपने वीजा के वैध होने के दौरान किसी भी समय यूके में प्रवेश कर सकते हैं और अपने प्रवास के दौरान किसी भी समय वहां से जा सकते हैं या वापस लौट सकते हैं।

पारस्परिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में, ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में रहने और काम करने के लिए समान वीजा की पेशकश की जाएगी।

इस योजना में वर्ष 2023 के लिए कुल 3,000 स्थान उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश स्थान फरवरी में आयोजित पहले मतदान में पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

शेष स्थानों का चयन चालू माह के मतपत्र से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।

मतपत्र में प्रवेश करना निःशुल्क है, लेकिन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल तभी भाग लें यदि वे वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं और वित्तीय और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को अपने वीजा के लिए आवेदन करने के छह महीने के भीतर यूके की यात्रा करनी होगी।

प्रश्न: उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है?

- (A) यूके-इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम

- (B) यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम
(C) भारत-यूके अध्ययन और कार्य पहल
(D) युवा गतिशीलता कार्यक्रम: भारत संस्करण

उत्तर: (B) यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम

तीन चिकित्सा संस्थानों में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए अब एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए 27 जून 2023 को तीन चिकित्सा संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीजीएचएस के सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान और प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं के बिना उन्नत उपचार सुविधाओं तक सीधी पहुंच होगी।

सुव्यवस्थित प्रक्रिया से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यक्तिगत दावों के निपटान में तेजी आएगी।

समझौते का उद्देश्य लंबी औपचारिकताओं को सरल बनाना और आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में तेजी लाना है।

सरकार की योजना मरीजों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्कृष्ट तृतीयक देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या का विस्तार करने की है।

प्रश्न : हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हुए हैं?

- (A) एम्स नई दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर
(B) एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जिपमर पुडुचेरी

(C) एम्स नई दिल्ली, अपोलो अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल

(D) एम्स नई दिल्ली, मैक्स हेल्थकेयर, मणिपाल हॉस्पिटल

उत्तर: (B) एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जिपमर पुडुचेरी

कृषि मंत्री ने ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 जून को फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग करके किसान घर बैठे बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के चेहरे को स्कैन करके आसानी से ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है।

ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने किसानों की ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक बढ़ा दिया है, ताकि प्रत्येक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सके।

पीएम किसान :

पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6,000 रुपये मिलेंगे। वार्षिक राशि सीधे तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं, जिनमें से 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं।

प्रश्न : भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है?

- (A) किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना
(B) कृषि उपकरणों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
(C) जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
(D) किसानों के बैंक खातों में एक मौद्रिक राशि हस्तांतरित करना

उत्तर : (D) किसानों के बैंक खातों में एक मौद्रिक राशि हस्तांतरित करने के लिए

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ अस्पताल में दाखिले की मंजूरी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जे) ने योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपये की राशि के साथ 5 करोड़ अस्पताल में दाखिले की उपलब्धि हासिल की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजना 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

AB PM-JAY को दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।

PM-JAY योजना के तहत, सत्यापित 23.39 करोड़ लाभार्थी देश भर के 28,351 सूचीबद्ध अस्पतालों में से किसी में भी 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

AB PM-JAY लाभार्थी 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

मेडिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर उपचार), आपातकालीन देखभाल, आर्थोपेडिक और यूरोलॉजी (गुर्दे से संबंधित रोग) शीर्ष तृतीयक देखभाल विशेषताएँ हैं जिनके तहत लाभार्थियों द्वारा अब तक उपचार प्राप्त किया गया है।

Qns : AB PM-JAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है?

- (A) 2 लाख रुपये
- (B) 3 लाख रुपये
- (C) 4 लाख रुपये
- (D) 5 लाख रुपये

उत्तर : (D) 5 लाख रुपये

पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई ने 8 साल पूरे किए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 9 मई 2023 को अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारंभ किया।

ये तीनों योजनाएं अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश का असंगठित क्षेत्र आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, दो बीमा योजनाएँ – PMJJBY और PMSBY शुरू कीं। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना-एपीवाई भी शुरू की।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) : पीएमजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती है। इसे साल-दर-साल रिन्यू किया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) : पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और साल-दर-साल नवीकरणीय है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और

संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRD(A) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

प्रश्न : 9 मई, 2015 को पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारंभ किसने किया?

- (A) भारत के राष्ट्रपति
- (B) भारत के प्रधान मंत्री
- (C) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
- (D) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

उत्तर : (B) भारत के प्रधान मंत्री

देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) का आयोजन कर रहा है।

शिक्षुता मेला का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करना और उनकी आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है।

इस आयोजन में भाग लेने और युवाओं को शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को आमंत्रित किया गया है।

भाग लेने वाली कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षुता प्रदान करती हैं।

यह आयोजन भाग लेने वाले संगठनों को संभावित शिक्षुओं से जुड़ने, मौके पर ही उनकी योग्यताओं में से चुनने और उन्हें शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम करेगा।

शिक्षुता मेला उन व्यक्तियों के लिए खुला है, जिन्होंने कक्षा 5 से कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई प्रमाणपत्र, डिप्लोमा प्रमाणपत्र हैं, या स्नातक हैं।

प्रश्न : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) क्या है?

- (A) स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए एमएसडीई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम
- (B) विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खोजने के लिए व्यक्तियों के लिए एक मंच

(C) शिक्षुता प्रशिक्षण में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी

(D) शिक्षुता नीतियों पर चर्चा करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के लिए एक सम्मेलन

उत्तर : (A) स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए एमएसडीई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम

अटल पेंशन योजना (APY) के तहत नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।

अटल पेंशन योजना (APY) ने 31 मार्च 2023 तक कुल नामांकन में 5.20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए ग्राहकों को शामिल करते हुए इस योजना में 20% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

एपीवाई में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) रुपये से अधिक है। 27,200 करोड़, और इस योजना ने अपनी स्थापना के बाद से 8.69% का निवेश प्रतिफल अर्जित किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) श्रेणी में, नौ बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने प्रति शाखा सौ से अधिक एपीवाई खाते खोले।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की श्रेणी के तहत, 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रति शाखा 160 से अधिक एपीवाई खाते खोले।

12 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की मदद से अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

अटल पेंशन योजना (APY):

APY के तहत, ग्राहकों को रुपये से लेकर गारंटीकृत पेंशन मिलती है। 1,000 से रु. 60 वर्ष की आयु से 5,000 प्रति माह, उनके योगदान के आधार पर।

अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को समान पेंशन मिलती है तथा दोनों अभिदाता पति/पत्नी की मृत्यु होने पर 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को दी जायेगी।

Qns : अटल पेंशन योजना (APY) क्या है?

- (A) आवास ऋण प्रदान करने की योजना।
- (B) एक स्वास्थ्य बीमा योजना।
- (C) एक पेंशन योजना।
- (D) शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना।

Ans : (C) एक पेंशन योजना।

मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'संगठन से समृद्धि' अभियान शुरू किया।

ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 'संगठन से समृद्धि' अभियान शुरू किया।

अभियान का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की तह में लाना है।

सरकार ने मौजूदा नौ करोड़ से 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।

एसएचजी सदस्यों की संख्या जो मई 2014 में सिर्फ 2.35 करोड़ थी, अब नौ करोड़ को पार कर गई है।

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि एसएचजी से जुड़ी हर महिला सालाना एक लाख रुपये कमा सके।

मंत्री ने महिलाओं से बाजरा उत्पादन करने का आग्रह किया।

Qns : ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है?

- a. समृद्धि से संगठन
- b. संगठन से समृद्धि
- c. सहयोग से समर्थन
- d. सम्मान से समाधान

Ans : b. संगठन से समृद्धि

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास।

18 अप्रैल, 2023 को जनजातीय मामलों के मंत्री, अर्जुन मुंडा ने मणिपुर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करके लाभान्वित करना है, अंततः जनजातीय कारीगरों की आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है।

पीटीपी-एनईआर योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों पर लागू होगी। पहल के हिस्से के रूप में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय कारीगरों के पैनल को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये मेले 18 अप्रैल को शुरू किए गए थे और आगे भी जारी रहेंगे।

Qns : जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू की गई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास का उद्देश्य क्या है?

- a. आदिवासी उत्पादों के व्यापार में शामिल बिचौलियों के लाभ मार्जिन को बढ़ाना।
- b. उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करना।
- c. आदिवासी उत्पादों के उत्पादन को भारत के एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित करना।
- d. भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।

Ans : b. उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करना।

उत्तरी सीमा पर गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' लॉन्च किया।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?

वित्त मंत्री द्वारा 2022 के बजट भाषण में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की घोषणा की गई थी।

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर उन गांवों को विकसित करना है जो अक्सर कम आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कारण विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपये सहित 4800 करोड़ रुपये के केंद्रीय घटकों के साथ 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को मंजूरी दी है।

वीवीपी के तहत, व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई है।

पहले चरण में प्राथमिकता कवरेज के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं।

भारत सरकार पहले से ही 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 117 सीमावर्ती जिलों के 460 सीमावर्ती ब्लॉकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0-10 किलोमीटर के भीतर स्थित बस्तियों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) लागू कर रही है।

बीएडीपी अपने दिशानिर्देशों के अनुसार गांव के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को मंजूरी देता है।

Qns : वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में नगरों का विकास करना।
- (B) मौजूदा योजनाओं को नए के साथ बदलने के लिए।
- (C) भारत के सभी गांवों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (D) उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना।

Ans : (D) उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 8वीं वर्षगांठ: 8 अप्रैल 2023

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म-उद्यमियों को आय-अर्जक गतिविधियों के लिए दस लाख रुपये तक के आसान संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा के लिए शुरू की गई थी।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं।

कुल ऋण का 21% नए उद्यमियों को स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण की आसान और परेशानी मुक्त पहुंच को सक्षम किया है और बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर साबित हुई है।

आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 8वीं वर्षगांठ है।

Qns: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है?

- (A) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म-उद्यमियों को आसान संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा के लिए एक योजना।
- (B) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की योजना।
- (C) किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना।
- (D) शहरी गरीबों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की योजना।

Ans : A. गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म-उद्यमियों को आसान संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा के लिए एक योजना।

भारत सरकार ने गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजना शुरू की।

भारत सरकार ने गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहायता नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है जो जुर्माना या जमानत राशि नहीं दे सकते हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश कैदी सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले समूहों से संबंधित हैं।

केंद्र उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो जुर्माना अदा न करने के कारण जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं।

गृह मंत्रालय जेलों में विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को हल करने और राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को साझा करने के लिए कई कदम उठा रहा है।

केंद्र जेलों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

Qns: कैदियों के लिए सहायता योजना से सबसे अधिक लाभ किसे होगा?

- A. अमीर कैदी
- B. सामाजिक रूप से सुविधा संपन्न समूह
- C. कम शिक्षा और आय के स्तर वाले सीमांत और वंचित कैदी।
- D. उच्च दंड या जमानत राशि वाले कैदी।
- C. कम शिक्षा और आय के स्तर वाले सीमांत और वंचित कैदी।

स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं।

जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

यह योजना विनिर्माण, सेवाओं, व्यापारिक क्षेत्रों और कृषि संबंधी गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करती है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 40,600 करोड़।

इस योजना ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस योजना ने उद्यमियों के असेवित/अल्प-सेवित वर्ग को किफायती ऋण प्रदान करके कई लोगों के जीवन को छुआ है।

इस योजना ने इच्छुक उद्यमियों को अपनी उद्यमशीलता कौशल दिखाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंख प्रदान किए हैं।

इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से कर्ज लेने वालों को अपना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन पोर्टल www.standupmitra.in संभावित उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

Qns : स्टैंड-अप इंडिया योजना किस तारीख को शुरू की गई थी?

- A. April 5, 2015
- B. April 6, 2016
- C. April 5, 2016
- D. April 6, 2015

Ans : C. April 5, 2016

भारत सरकार ने पांच करोड़ गैर-साक्षरों को लक्षित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ नया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया।

भारत सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है।

इस योजना का वित्तीय परिव्यय एक हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा और इसे 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा।

इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ निरक्षरों को लक्षित करना है।

लाभार्थियों की पहचान एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके सर्वेक्षकों द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाएगी।

गैर-साक्षर भी किसी भी स्थान से सीधे मोबाइल एप के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

Qns : न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है?

- (A) सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना।
- (B) ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल।
- (C) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम।
- (D) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को लक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना।

Ans : (D) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को लक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना।

आईएनएस चिल्का के अग्निवीरों के पहले बैच ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है।

ओडिशा के आईएनएस चिल्का से पहली बैच के अग्निवीर भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

28 मार्च 2023 को नौसेना के मुख्य अधिकारी एडमिरल आर हरिकुमार, पी टी उषा और मिथाली राज जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया।

बैच में 273 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने आईएनएस चिल्का में 16 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण लिया।

परेड में बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों, विशेष आमंत्रितों और अग्निवीरों के माता-पिता और अभिभावकों ने भाग लिया।

योजना के प्रति प्रारंभिक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद, युवा अग्निवीरों ने अपने देश की सेवा करने के लिए आत्मविश्वास और उत्सुकता का प्रदर्शन किया, जिससे पासिंग आउट परेड एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।

Qns : INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे?

- (A) पी टी उषा
- (B) मिथाली राज
- (C) एडमिरल आर हरिकुमार
- (D) रक्षा कर्मिक

Ans : (C) एडमिरल आर हरिकुमार

सरकार ने कहा, 11 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2.18 करोड़ पक्के मकान बनाए गए।

सरकार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 11 मार्च तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के घर बनाए जा चुके हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही लाभार्थियों को आवंटित कुल 2.94 करोड़ घरों में से 2.85 करोड़ पक्के घरों को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने मार्च 2024 तक दो करोड़ 95 लाख पक्के घरों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना '2022 तक सबके लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के 2 घटक हैं – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसे मार्च 2016 में नया नाम दिया गया था।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं।

24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के 4 साल पूरे हो गए हैं।

भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी, 2019 को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था।

पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में हर साल तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम (पीएमकेकेके) का नाम अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना रखा गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 15 दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम (पीएमकेकेके) का नाम अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना रखा गया है।

एकीकृत योजना मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है। सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल।

इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।



Qns : हाल ही में सरकार द्वारा पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है?

- A. नंदी पोर्टल
- B. सुधा पोर्टल
- C. धेनु पोर्टल
- D. सुरभि पोर्टल

उत्तर: ए - नंदी पोर्टल

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल के लॉन्च के साथ पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इसका उद्देश्य आवेदनों पर समय पर कार्रवाई करना और इन आवश्यक उत्पादों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करना है।

Qns : किस राज्य में 'ऑपरेशन कन्विकशन' शुरू किया गया है?

- A. हरियाणा
- B. उत्तर प्रदेश
- C. राजस्थान Rajasthan
- D. गुजरात

उत्तर: बी - उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध से निपटने के लिए 'ऑपरेशन कन्विकशन' नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है।

इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धार्मिक रूपांतरण और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों जैसे जघन्य अपराधों में सजा की प्रक्रिया को तेज करना है।

Qns : हाल ही में किस राज्य में 'गृह ज्योति योजना' शुरू की गई है?

- A. हरियाणा
- B. उत्तर प्रदेश

- C. कर्नाटक
- D. ओडिशा

उत्तर: सी - कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है।

यह योजना राज्य की महत्वाकांक्षी "सभी के लिए आवास" योजना का एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करना है।

Qns : 'लाडली बहना योजना' किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. हरियाणा
- B. राजस्थान Rajasthan
- C. महाराष्ट्र
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर: डी - मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के गैरीसन ग्रांड में आयोजित राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ाना है।

Qns : 'मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना' किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. हरियाणा
- B. राजस्थान Rajasthan
- C. महाराष्ट्र
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर: डी - मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'सीएम सीखो और कमाओ योजना' शुरू की गई है।

इस पहल का लक्ष्य 100,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम नए कौशल प्राप्त करने के अलावा 8,000 रुपये से 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करता है।

इस योजना के लिए कुल 703 प्रशिक्षण क्षेत्रों की पहचान की गई है।

Qns : 'नंद बाबा मिल्क मिशन योजना' किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. गुजरात
- B. उत्तर प्रदेश
- C. हरियाणा
- D. राजस्थान Rajasthan

उत्तर: बी - उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया गया है।

इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने का अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

Qns : नमो शेतकारी महासमान योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. उत्तर प्रदेश।
- B. राजस्थान Rajasthan
- C. महाराष्ट्र
- D. तेलंगाना

उत्तर: सी - महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है।

मो शेतकारी महासंजन योजना के तहत, महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान मिलेगा।

इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।

Qns : किस राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है?

- A. महाराष्ट्र
- B. तेलंगाना
- C. उत्तर प्रदेश
- D. हरियाणा

उत्तर: बी - तेलंगाना

तेलंगाना सरकार ने एक नई नीति पेश की है जिसे राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है।

इसे एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान करना, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है।

Qns : ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना किस राज्य में लागू की जाएगी?

- A. महाराष्ट्र
- B. केरल
- C. तेलंगाना
- D. कर्नाटक

उत्तर: सी - तेलंगाना

तेलंगाना सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए 'गीता कार्मिकुला भीम' नामक एक नई बीमा योजना की घोषणा की है।

इसका उद्देश्य खेतों में ताड़ के पेड़ों से ताड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले ताड़ी उत्पादक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

नई बीमा योजना ताड़ी निकालने वाले परिवारों को कई लाभ प्रदान करेगी।

Qns : हाल ही में किसकी सुरक्षा के लिए 'मिष्ठी योजना' शुरू की गई है?

- A. सदाबहार
- B. चीता
- C. पांडा
- D. पश्चिमी घाट

उत्तर: डी - मेंगोव

केंद्रीय बजट 2023-24 में मेंगोव संरक्षण के लिए मिष्ठी योजना शुरू की गई है।

मिष्ठी योजना का उद्देश्य आस-पास के समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देते हुए, भारतीय तट के साथ मेंगोव पारिस्थितिकी को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है।

Qns : 'एक पंचायत, एक खेल का मैदान' परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. हरियाणा
- B. गुजरात
- C. उत्तर प्रदेश
- D. केरल

उत्तर: डी - केरल

19 अप्रैल 2023 को, केरल सरकार ने प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 'एक पंचायत, एक खेल का मैदान' परियोजना शुरू की है।

इस पहल का लक्ष्य राज्य भर के लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण खेल के मैदानों की कमी को दूर करना है।

Qns : हाशिए पर रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?

- A. संगठन से वृद्धि
- B. वृद्धि से समृद्धि
- C. संगठन से समृद्धि
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: सी - संगठन से समृद्धि

ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में लाने के लिए 'संगठन से समृद्धि' योजना शुरू की है।

सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

Qns : वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो गये हैं?

- A. आठ
- B. दो
- C. चार
- D. दस

उत्तर: सी - चार

24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं।

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी।

इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

Qns : केंद्र सरकार ने 'पीएम कुसुम योजना' की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है?

- A. जून 2025
- B. मार्च 2026
- C. मार्च 2024
- D. जनवरी 2026

उत्तर: बी - मार्च 2026

केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।

इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी।

इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था।

पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप सिस्टम से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

Qns : किस राज्य सरकार ने 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' परियोजना शुरू की है?

- A. हरियाणा
- B. पंजाब
- C. राजस्थान Rajasthan
- D. उत्तर प्रदेश

उत्तर: बी - पंजाब

पंजाब सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' शुरू की है।

इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ-साथ छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

'स्कूल ऑफ एमिनेंस' प्रोजेक्ट के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

Qns : अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?

- A. हरियाणा
- B. महाराष्ट्र
- C. गुजरात
- D. राजस्थान Rajasthan

उत्तर: डी - राजस्थान

राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा देश में पहली बार 'दृष्टि का अधिकार' के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है।

यह नीति राज्य में दृष्टिबाधित तीन लाख से अधिक लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से लायी गयी है।

Qns : हाल ही में किस राज्य में साझा स्कूल बस प्रणाली, महत्वपूर्ण पर्यटक वाहन और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजनाएं शुरू की गई हैं?

- A. हरियाणा
- B. मेघालय
- C. सिक्किम
- D. महाराष्ट्र

उत्तर: बी - मेघालय

मेघालय के मुख्यमंत्री कौनराड संगमा ने कॉमन स्कूल बस प्रणाली, महत्वपूर्ण पर्यटन वाहन और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री ने साझा स्कूल बसों को हरी झंडी दिखाई और उम्मीद जताई कि इससे शिलांग में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

Qns : 'सहर्ष' विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है?

- A. त्रिपुरा
- B. पश्चिम बंगाल
- C. मध्य प्रदेश
- D. राजस्थान Rajasthan

उत्तर: ए - त्रिपुरा

त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'सहर्ष' विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है।

इसका उद्देश्य बच्चों को खुशी और उत्साह के साथ पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है।

इसे अगस्त 2022 में राज्य के 40 स्कूलों में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा।

Qns : किस राज्य में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक वर्ष तक चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा?

- A. मध्य प्रदेश
- B. हरियाणा
- C. केरल
- D. ओडिशा

उत्तर: डी - ओडिशा

ओडिशा सरकार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। योजना के तहत बीपीएल परिवार में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

Qns : किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है?

- A. मध्य प्रदेश
- B. हरियाणा
- C. केरल
- D. ओडिशा

उत्तर: ए - मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किये।

प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत घर बनाने के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा।

Qns : किस राज्य में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया है?

- A. उत्तराखंड
- B. हिमाचल प्रदेश
- C. अरुणाचल प्रदेश
- D. गुजरात

उत्तर: बी - हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है।

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।

Qns : 'हर घर गंगाजल' परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. बिहार
- B. उत्तराखंड
- C. उत्तर प्रदेश
- D. पश्चिम बंगाल

उत्तर: ए - बिहार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगाजल परियोजना की शुरुआत की है।

राज्य के सूखे इलाकों में गंगा का जल नल से उपलब्ध कराने की यह एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है।

इस योजना से मानसून के दौरान गंगा के अतिरिक्त जल का संचयन करने में मदद मिलेगी।

हर घर गंगाजल बिहार सरकार की जल, जीवन, हरियाली योजना का एक हिस्सा है।

Qns : 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी' योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. पंजाब
- B. उत्तराखंड
- C. सिक्किम

D. आंध्र प्रदेश

उत्तर: बी - उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर को इगास पर्व पर 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी' योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य है।

इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

Qns : किस राज्य में 'महिला मैत्रीपूर्ण पर्यटन' परियोजना शुरू की गई है?

- A. गुजरात
- B. हिमाचल प्रदेश
- C. केरल
- D. सिक्किम

उत्तर: सी - केरल

केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ गंतव्य सुनिश्चित करने के लिए 'महिला-अनुकूल पर्यटन' परियोजना शुरू की है।

पूरी तरह से महिला टूर पैकेज, जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल हैं, का प्रबंधन और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

परियोजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में पर्यटन स्थल महिला पर्यटकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

Qns : 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' योजना किसने शुरू की है?

- A. नरेंद्र सिंह तोमर
- B. अमित शाह
- C. नरेंद्र मोदी
- D. मनसुख मंडाविया

उत्तर: सी - नरेंद्र मोदी

वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में की है।

इससे कंपनियों को भारत में एक ही ब्रांड नाम (भारत ब्रांड) के तहत उर्वरकों का विपणन करने में मदद मिलेगी।

यह योजना किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराएगी।

Qns : निम्नलिखित में से किसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'हिमकैड' योजना शुरू की है?

- A. किसान
- B. मजदूर
- C. स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- D. ऊपर के सभी

उत्तर: ए - किसान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'हिमकैड' नाम से एक नई योजना शुरू की है।

इसके तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियाँ प्रदान करने की योजना है।

यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को अंत तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

Qns : किस राज्य में वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई है?

- A. राजस्थान Rajasthan
- B. तमिलनाडु
- C. ओडिशा
- D. महाराष्ट्र

उत्तर:-ओडिशा

ओडिशा सरकार ने हाल ही में छटा योजना यानी सामुदायिक संचयन और छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल संचयन शुरू की है।

राज्य क्षेत्र की योजना शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करेगी।

Qns : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. हरियाणा
- B. महाराष्ट्र
- C. राजस्थान Rajasthan
- D. गुजरात

उत्तर: सी - राजस्थान

राजस्थान में 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इसकी शुरुआत की।

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

Qns : किस राज्य सरकार ने 'पुधुमई पेन योजना' शुरू की है?

- A. तेलंगाना
- B. तमिलनाडु
- C. केरल
- D. आंध्र प्रदेश

उत्तर: बी - तमिलनाडु

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह में 'पुधुमई पेन' नामक मूलुर रामामिर्थम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है।

पुधुमई पेन योजना के तहत, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा V से XII तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1,000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा।

Qns : नई अनुसंधान छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजना किसने शुरू की है?

- A. यूजीसी
- B. गृह मंत्रालय
- C. सीबीएसई
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: ए - यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस पर नई शोध छात्रवृत्ति और शोध अनुदान योजनाएं शुरू कीं।

एकल बालिका के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉ. राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों फेलोशिप, सेवारत संकाय सदस्यों के लिए अनुसंधान अनुदान और डॉ. डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान।

Qns : हाल ही में लॉन्च की गई 'पीएम-श्री' योजना किस क्षेत्र से संबंधित योजना है?

- A. खेल
- B. बैंकिंग
- C. शिक्षा
- D. अनाज

उत्तर: सी - शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना की घोषणा की है।

इसके तहत देशभर के 14 हजार 500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा।

पीएम-श्री स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से शिक्षा दी जाएगी।

Qns : 'मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना' किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. हिमाचल प्रदेश
- B. उत्तराखंड

C. हरियाणा

D. पंजाब

उत्तर: बी - उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की।

उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना से कुल 3900 बालक-बालिकाओं को लाभ मिलेगा।

Qns : हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं?

A. आठ

B. सात

C. पाँच

D. चार

उत्तर: ए - आठ

मौजूदा केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आठ साल पूरे कर लिए हैं।

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।

इसका उद्देश्य वंचित कमजोर वर्गों तक विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत बैंक खातों की उपलब्धता, आवश्यकता-आधारित ऋण तक पहुंच, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना था।

Qns : 'ग्राम रक्षा रक्षक योजना 2022' किस राज्य में लागू की गई है?

A. छत्तीसगढ़

B. जम्मू और कश्मीर

C. पंजाब

D. तेलंगाना

उत्तर: जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने ग्राम रक्षा रक्षक योजना 2022 के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य जम्मू-कश्मीर के गांवों में आतंकवाद से निपटने और सेना की मदद के लिए काम करेंगे।

Qns : शहरों और नगर पालिकाओं को भीख मांगने से मुक्ति दिलाने के लिए 'SMILE' कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है?

A. मुंबई

B. कोलकाता

C. नई दिल्ली

D. चंडीगढ़

उत्तर: सी - नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में 'स्माइल: आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों को समर्थन' पहल शुरू की है।

इसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है।

मंत्रालय ने कहा कि पचहत्तर नगर निगम भिखारियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी कदम उठाएंगे।

Qns : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है?

A. 2030

B. 2027

C. 2025

D. 2024

उत्तर: डी - 2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास मिशन को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की यह योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी।

Qns : किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है?

- A. राजस्थान Rajasthan
- B. हरियाणा
- C. उत्तर प्रदेश
- D. पंजाब

उत्तर: बी - हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग)' योजना शुरू की है।

सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को 'बजट' निजी स्कूलों में 'मुफ्त शिक्षा' प्रदान करने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है, वे निजी स्कूलों में कक्षा 2 से कक्षा 12 तक प्रवेश ले सकते हैं।

Qns : किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है?

- A. उत्तर प्रदेश
- B. पंजाब
- C. हरियाणा
- D. केरल

उत्तर: डी - केरल

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है।

यह परियोजना राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके।

केरल की आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है।

Qns : निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा लाभ के लिए एक योजना शुरू की?

- A. कर्नाटक
- B. तमिलनाडु
- C. उत्तर प्रदेश
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर-सी - उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है।

उद्देश्य- राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

Qns : हाल ही में किस राज्य ने दलित सशक्तिकरण के लिए "दलित बंधु" योजना शुरू की है?

- A. हरियाणा
- B. मध्य प्रदेश
- C. तेलंगाना
- D. कर्नाटक

उत्तर-सी-तेलंगाना

तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि तेलंगाना दलित बंधु योजना को पायलट आधार पर चयनित विधानसभा क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

इसके तहत बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 'तेलंगाना दलथा बंधु' योजना को लागू करने के लिए हुजूरबाद विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है।

Qns : किस राज्य सरकार ने बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वर्णबीर नारी योजना शुरू की है?

- A. कर्नाटक
- B. असम
- C. तेलंगाना

D. मध्य प्रदेश

उत्तर: बी - असम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी, असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए 'स्विनीभर नारी' योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी।

Qns : हाल ही में सरकार ने कितने राज्यों में "नशा मुक्त भारत अभियान" शुरू किया है?

- A. 200
- B. 272
- C. 252
- D. 352

उत्तर: बी - 272

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करना शुरू किया।

Qns : निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) की भागीदारी बढ़ाने के लिए सह-भागिता योजना शुरू की है?

- A. दिल्ली
- B. महाराष्ट्र
- C. पुदुचेरी
- D. चंडीगढ़

उत्तर:- ए- दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के विलय के बाद संपत्ति कर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है।

एलजी ने कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में आवासीय कल्याण संघों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सह-भागिता योजना शुरू की है।

Qns : 'अर्न विद लर्न' योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

- A. पंजाब
- B. तेलंगाना
- C. उत्तराखंड
- D. त्रिपुरा

उत्तर: डी - त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ने वाले लोगों को वापस लाने के लिए 'अर्न विद लर्न' नाम से एक नई योजना शुरू की है।

यह योजना 'विद्यालय चलो अभियान' का एक हिस्सा है। इसके तहत प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे यदि वे किसी ड्रॉपआउट छात्र का उसी स्कूल में नामांकन कराते हैं।

Qns : प्री-प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है?

- A. पंजाब
- B. तेलंगाना
- C. उत्तराखंड
- D. त्रिपुरा

उत्तर: सी - उत्तराखंड

केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 'बाल वाटिका' का उद्घाटन करके इस प्रक्रिया की शुरुआत की है।

Qns : निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करेगा?

- A. हरियाणा
- B. मेघालय

- C. त्रिपुरा
D. तेलंगाना

उत्तर: बी - मेघालय

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने घोषणा की है कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

Qns : किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 'मिशन कुशल कर्मी' नामक योजना शुरू की है?

- A. चंडीगढ़
B. गुजरात
C. हरियाणा
D. दिल्ली

उत्तर: डी - दिल्ली

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। कार्यक्रम को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) और दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सहयोग से विकसित किया गया है।

Qns : निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 'नारी को नमन' नामक एक नई योजना शुरू की है?

- A. हिमाचल प्रदेश
B. हरियाणा
C. पंजाब
D. झारखंड

उत्तर: ए - हिमाचल प्रदेश

इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा की गई है।

इसका लक्ष्य राज्य के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना है।

Qns : भारत सरकार एनडीपीएस को वित्त मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित करेगी?

- A. गृह मंत्रालय
B. विदेश मंत्रालय
C. रक्षा मंत्रालय
D. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर: ए - गृह मंत्रालय

भारत सरकार कथित तौर पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

Qns : श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है?

- A. निपुण
B. Saksham
C. दक्ष
D. प्रवीण

उत्तर: ए - निपुण

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव राष्ट्रीय स्तर की परियोजना - निपुण लॉन्च की है।

इस योजना का लाभ विदेशों में भी श्रमिकों को मिलेगा।

Qns : ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है?

- A. पंजाब
B. हरियाणा
C. हिमाचल प्रदेश
D. राजस्थान Rajasthan

उत्तर: सी - हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022' को मंजूरी दे दी है।

इस नई ड्रोन नीति के साथ, हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

Qns : निम्नलिखित में से किस राज्य में 'लोक मिलानी' योजना शुरू की गई है?

- A. पंजाब
- B. हरियाणा
- C. गुजरात
- D. महाराष्ट्र

उत्तर: ए - पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोक मिलानी जन संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है।

यह अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है।

Qns : राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता-एनईएलएस पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है?

- A. मुंबई
- B. नई दिल्ली
- C. चंडीगढ़
- D. कोलकाता

उत्तर: बी - नई दिल्ली

स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है।

इसे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है।

डॉ. भारती पवार ने कहा कि एनईएलएस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति को मूर्त रूप देते हुए एक उच्च मानक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

Qns : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य की स्टार्टअप नीति और पोर्टल लॉन्च किया है?

- A. मध्य प्रदेश
- B. उत्तर प्रदेश
- C. हिमाचल प्रदेश
- D. आंध्र प्रदेश

उत्तर: ए - मध्य प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया, जो राज्य में स्टार्टअप उद्यमों के लिए माहौल बनाने में मदद करेगा।

Qns : किस राज्य सरकार ने 'लाइली लक्ष्मी योजना' का दूसरा चरण शुरू किया है?

- A. हरियाणा
- B. असम
- C. ओडिशा
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर: डी - मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है।

इसके तहत अगर लाइली लक्ष्मी लड़कियों को मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम मिलेगा। और यदि वे अन्य संस्थानों में प्रवेश लेते हैं तो उनकी पूरी फीस सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।

मध्य प्रदेश में हर साल 2 मई से 12 मई तक लाइली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है।

Qns : भारत की पहली 'आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला' की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है?

- A. झारखंड

- B. ओडिशा
- C. मध्य प्रदेश
- D. त्रिपुरा

उत्तर: बी - उड़ीसा

एसटी और एससी विकास विभाग ने जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर के साथ बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगी।

Qns : किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना 'जीवाला' शुरू की है?

- A. महाराष्ट्र
- B. आंध्र प्रदेश
- C. तेलंगाना
- D. नागालैण्ड

उत्तर: ए - महाराष्ट्र

महाराष्ट्र जेल विभाग ने उन कैदियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा जीवन्मया योजना शुरू की है जो तीन साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं।

इस योजना के तहत, कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी फीस या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं।

Qns : हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है?

- A. छत्तीसगढ़
- B. बिहार
- C. मणिपुर
- D. पंजाब

उत्तर: ए - छत्तीसगढ़

इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इसके तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

Qns : किस राज्य सरकार ने निमोनिया की सफलतापूर्वक रोकथाम के लिए 'सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (SAANS)' अभियान शुरू किया है?

- A. हरियाणा
- B. पश्चिम बंगाल
- C. कर्नाटक
- D. ओडिशा

उत्तर: सी - कर्नाटक

यह अभियान पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का शीघ्र पता लगाने और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। यह मुख्य रूप से वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है।

Qns : निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने पर विचार कर रही है?

- A. हरियाणा
- B. गुजरात
- C. पंजाब
- D. महाराष्ट्र

उत्तर: डी - महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा है कि कृषि को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में माना जा रहा है।

Qns : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या कब तक बढ़ाकर दस हजार करने का लक्ष्य रखा है?

- A. अक्टूबर 2022
- B. मार्च 2023
- C. दिसंबर 2023
- D. मार्च 2024

उत्तर: डी - मार्च 2024

केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर दस हजार करने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराना है।

Qns : हाल ही में किस राज्य ने 'जन निगरानी' ऐप लॉन्च किया है?

- A. जम्मू और कश्मीर
- B. उत्तर प्रदेश
- C. तेलंगाना
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर: ए - जम्मू और कश्मीर

यह ऐप ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है।

इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है।

Qns : स्वास्थ्य मंत्रालय किस स्तर पर आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है?

- A. ज़िला
- B. अवरोध पैदा करना
- C. गाँव
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: बी - ब्लॉक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देशभर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले एक लाख से अधिक आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे।

Qns : निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए "हिम प्रहरी" नामक योजना शुरू करेगा?

- A. अरुणाचल प्रदेश
- B. सिक्किम
- C. हिमाचल प्रदेश
- D. उत्तराखंड

उत्तर: सी - उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार 'हिम प्रहरी' योजना लागू करने के लिए तैयार है जो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार इस योजना को उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है।

Qns : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

- A. 2024
- B. 2026
- C. 2028
- D. 2030

उत्तर: बी - 2026

केंद्र सरकार ने 5,911 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को चार साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अभियान को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

Qns : हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी है?

- A. 2023
- B. 2024
- C. 2026
- D. 2030

उत्तर: A- 2023

अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना 2015 में नीति आयोग के तहत की गई है। एआईएम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्योगों के स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना है।

Qns : निम्नलिखित में से किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'हॉबी हब' स्थापित करने की योजना शुरू की?

- A. दिल्ली सरकार
- B. राजस्थान सरकार
- C. हरियाणा सरकार
- D. हिमाचल सरकार

उत्तर: ए - दिल्ली सरकार

दिल्ली में नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शौक केंद्र स्थापित करने की एक परियोजना चल रही है।

शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए यह परियोजना केवल एक पाली वाले सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी।

Qns : हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' नामक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है?

- A. राजस्थान Rajasthan
- B. हरियाणा
- C. मध्य प्रदेश

D. पंजाब

उत्तर: बी - हरियाणा

यह योजना सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है, जो किसानों को चार श्रेणियों 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत एकड़ के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।

इस योजना में 21 फसलें शामिल हैं - 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल।

Qns : निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना शुरू की है?

- A. राजस्थान Rajasthan
- B. महाराष्ट्र
- C. झारखंड
- D. केरल

उत्तर: ए - राजस्थान

राज्य सरकार ने राज्य की सभी महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की। जिसमें सभी महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन दिए जाएंगे। जिससे वे कई बीमारियों से बचे रहेंगे साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

Qns : हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा वाहन नामक गश्ती टीमों का गठन किया है?

- A. हरियाणा
- B. असम
- C. आंध्र प्रदेश
- D. कर्नाटक

उत्तर: सी - आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए

प्रतिक्रिया समय का पालन करने और उसमें सुधार करने के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में 1.16 करोड़ महिलाओं ने दिशा ऐप डाउनलोड किया है और सभी दिशा गश्ती वाहन जीपीएस के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए हैं, जहां कर्मचारी शहरों में 4-5 मिनट और गांवों में 8-10 मिनट में जवाब देंगे।

Qns : मॅटर ऑफ द कंट्री नामक योजना किस सरकार की पहल है?

- A. हरियाणा सरकार
- B. मध्य प्रदेश सरकार
- C. दिल्ली सरकार
- D. कर्नाटक सरकार

उत्तर: सी - दिल्ली सरकार

18 से 35 वर्ष की आयु के लोग एक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम के तहत सलाहकार बनने के लिए साइन अप कर सकते हैं।

ऐप को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था।

यह ऐप छात्रों को उनके आपसी हितों के आधार पर जोड़ेगा।

Qns : निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A. तेलंगाना
- B. आंध्र प्रदेश
- C. ओडिशा
- D. पश्चिम बंगाल

उत्तर: सी - ओडिशा

नाबार्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।

यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह जिला स्तरीय ऋण योजनाएँ तैयार करता है ताकि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को मार्गदर्शन और प्रेरित किया जा सके।

यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी भी करता है और उन्हें सीबीएस प्लेटफॉर्म (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन) से जुड़ने में भी मदद करता है।

Qns : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?

- A. हरियाणा
- B. मिजोरम
- C. सिक्किम
- D. ओडिशा

उत्तर:-डी-ओडिशा

माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 2022 को ओडिशा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 (आईएमआई) लॉन्च किया गया था।

ओडिशा के 20 जिलों में पूर्ण टीकाकरण 90% से ऊपर पाया गया और शेष 10 जिलों में 90% से कम पाया गया।

Qns : भारत और हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD-PR) ने महिला और बाल कल्याण से संबंधित परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता किया है?

- A. विश्व बैंक
- B. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C. यूनिसेफ
- D. एशियाई बैंक

उत्तर: सी - यूनिसेफ

यूनिसेफ, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह एजेंसी 192 देशों और क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ दुनिया में सबसे व्यापक और मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है।

मुख्यालय: न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रमुख: कैथरीन एम. रसेल

Qns : "दलित बंधु" नामक लोकप्रिय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख सामाजिक उत्थान है?

- A. तमिलनाडु
- B. असम
- C. तेलंगाना
- D. मध्य प्रदेश

उत्तर: सी - तेलंगाना

तेलंगाना राज्य के बजट में, सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रमुख दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपये आवंटित किए।

इसके अलावा, वित्तीय संकट से बचने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में दलित बंधु लाभार्थियों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा एक दलित रक्षा निधि (सुरक्षा कोष) भी स्थापित की गई है।

Qns : हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय ने कथित अनियोजित विकास और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जल निकायों के गायब होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया है?

- A. भोपाल
- B. मानव अधिकार आयोग
- C. दिल्ली उच्च न्यायालय
- D. सुप्रीम कोर्ट

उत्तर: ए - मानवाधिकार आयोग

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था।

यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021) इसके वर्तमान अध्यक्ष का पद जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा संभाल रहे हैं। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष (जो भी पहले हो) होता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर की जाती है।

Qns : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और निजी क्षेत्रों को गति शक्ति परियोजना को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी है, यह योजना कब शुरू की गई थी?

- A. 15 अगस्त 2021
- B. 26 जनवरी, 2021
- C. 15 अगस्त 2020
- D. 26 जनवरी, 2022

उत्तर: ए - 15 अगस्त, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना का उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे के विकास के सभी पहलुओं के बीच समन्वय बनाकर काम करना है।

गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगने वाले समय को कम करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दो लाख किलोमीटर तक बढ़ाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की मदद से विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा।

Qns : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान डिजिटल मिशन के लिए अगले पांच साल के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी गई है?

- A. 500 करोड़
- B. 900 करोड़
- C. 1200 करोड़
- D. 1600 करोड़

उत्तर: D - 1600 करोड़

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का लक्ष्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक रीढ़ विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी जो उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं खरीद सकते।

Qns : हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू कर दिया है?

- A. तेलंगाना
- B. आंध्र प्रदेश
- C. मध्य प्रदेश
- D. राजस्थान Rajasthan

उत्तर: डी - राजस्थान

पुरानी पेंशन योजना के अनुसार कर्मियों को अंतिम मूल वेतन का 50% तक पेंशन दी जाती है, साथ ही 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी लागू होता है।

नई पेंशन योजना में ऐसी कोई गारंटी नहीं है और न ही महंगाई भत्ता लागू होता है।

अप्रैल 2005 के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्तियों में पुरानी पेंशन बंद कर दी थी।

Qns : विकासशील देशों में जल प्रबंधन और सतत विकास में लैंगिक मुद्दों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है?

- A. मैसूर
- B. जयपुर
- C. मुंबई
- D. सूरत

उत्तर: ए - मैसूर

इसका आयोजन मैसूर के जेएसएस मेडिकल कॉलेज में किया गया है।

जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (जेएसएसएएचईआर), मैसूर, गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ साझेदारी में कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

कार्यशाला में विकासशील देशों में जल संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा।